हिंदुस्तान आइडियल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

बनाम

भारतीय जीवन बीमा निगम

12 अप्रैल, 1962

[ए.के. सरकार, के. सुब्बाराव, जे.आर. मुधोलकर, जे.जे.]

बीमा--"संदर्भ देने वाला व्यक्ति"- का अर्थ- निगम की ओर रुख करने के लिए कोई निर्धारित अवधि नहीं- प्रभाव- जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (31/1956), धारा 16(2) 48 (2) (एफ)- जीवन बीमा निगम नियम, 1956, नियम 12 उप-नियम (i), (ii), (iii)

बीमाकर्ता आंध्रा इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का जीवन बीमा व्यवसाय भारतीय जीवन बीमा निगम में निहित हो गया और यह जीवन बीमा निगम अधिनियम की धारा 16 के तहत मुआवजे का हकदार बन गया। निगम ने एक प्रस्ताव रखा और विभिन्न कटौतियों का दावा किया। बीमाकर्ता ने कुछ विवाद उठाए और 6 अगस्त, 1957 को मुआवजे के पुनर्मूल्यांकन के लिए और इसके गठन की तारीख से तीन महीने तक आवेदन करने के लिए समय बढ़ाने के लिए 25 मई, 1957 को गठित न्यायाधिकरण में एक आवेदन किया। 21 सितम्बर 1937 को, बीमाकर्ता ने

अपने दावे का विवरण देते हुए एक और बयान दाखिल किया। दावे के जवाब में निगम ने अपना लिखित बयान दाखिल किया। न्यायाधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम के तहत विरचित नियमवाली के नियम 12 के तहत मुआवजा का दावा समय-बाधित था और आवेदन को खारिज कर दिया। यह भी अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 16(2) के तहत बीमाकर्ता को कोई अधिकार नहीं था कि वह मुआवजे के दावे के लिए सीधे न्यायाधिकरण की शरण में जाये, बल्कि निगम को विवाद का संदर्भ न्यायाधिकरण में भेजने के लिए कहा जा सकता था और उसने न्यायाधिकरण को संदर्भ भेजने के लिए समय बढ़ाने का कोई कारण नहीं दिखाया। न्यायाधिकरण के निर्णय के खिलाफ, बीमाकर्ता ने विशेष अनुमति प्राप्त की और उसके बाद हिंदुस्तान आइडियल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ विलय कर लिया, जिसे बीमाकर्ता के स्थान पर अपीलकर्ता के रूप में प्रतिस्थापित किया गया।

अभिनिर्धारित किया गया, (सुब्बा राव और मुधोलकर, जे.जे. के अनुसार) जबकि धारा 48 की उपधारा (1) केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करती है, धारा 16 की उपधारा (2) उस पर एक कर्तव्य लगाती है और इसलिए, केंद्र सरकार के लिए वह अवधि निर्धारित करना अनिवार्य है जिसके भीतर बीमाकर्ता को दावे को न्यायाधिकरण में भेजने के लिए निगम का रुख करना होगा। जब कानून को किसी कार्य को करने के लिए

एक अवधि निर्धारित करने की आवश्यकता होती है, तो उस अवधि को विशेष उद्देश्य के विशिष्ट संदर्भ में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। धारा 16 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट विशिष्ट उद्देश्य मामले को निर्णय के लिए न्यायाधिकरण के पास भेजना है। "इस प्रकार संदर्भ बनाना निगम के हाथ में है न कि बीमाकर्ता के हाथ में जो केवल संदर्भ बनाने के लिए निगम की ओर रुख कर सकता है। बीमाकर्ता को निगम की ओर रुख करने में सक्षम बनाने के लिए समय निर्धारित करना होगा। संदर्भ देने के लिए समय निर्धारित करना निगम को स्थानांतरित करने के लिए समय निर्धारित करना नहीं है। निहितार्थ द्वारा समय निर्धारित करना धारा 16 की उपधारा (2) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं होगा।

वेस्ट डर्बी यूनियन बनाम मेट्रोपॉलिटन लाइफ एश्योरेंस कंपनी [1897] ए.सी. 647, संदर्भित।

नियम 12 बनाते समय नियम बनाने वाले प्राधिकारी ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि धारा 16 की उपधारा (2) बीमाकर्ता द्वारा नहीं बल्कि निगम द्वारा एक संदर्भ पर विचार करती है। इसलिए न्यायाधिकरण के समक्ष की गई कार्यवाही गलत समझी गई। सीमा का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि वह अवधि जिसके भीतर बीमाकर्ता को संदर्भ बनाने के लिए निगम को स्थानांतरित करना होगा, धारा 16 की उपधारा (2) के अनुसार अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। ऐसी अवधि निर्धारित होने

के बाद अपीलकर्ता धारा 16(2) के तहत निगम की ओर रुख करने के लिए स्वतंत्र होगा। बीमाकर्ता द्वारा आग्रह किया गया था कि दावे को समय से बाधित नहीं माना जा सकता है और यह नियम 12 के प्रावधान के तहत समय के विस्तार के लिए एक उपयुक्त मामला था।

अभिनिर्धारित किया गया, नियम 12 के अनुसार, स्वयं पढ़ने से यह स्पष्ट नहीं होता है कि यह निगम पर लागू होता है या बीमाकर्ता या मुख्य एजेंट या विशेष एजेंट पर लागू होता है, उस नियम के मुख्य प्रावधानों के दायरे को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान पर गौर करना स्वीकार्य है। परंतुक के साथ इसे पढ़ने से नियमों के गठन के किसी भी स्वीकृत नियम का उल्लंघन नहीं होगा।

अभिनिर्धारित किया गया (सरकार, जे. द्वारा), कि बीमाकर्ता को सीधे न्यायाधिकरण में जाने का कोई अधिकार नहीं था और न्यायाधिकरण के समक्ष उसके द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पूरी तरह से गलत थी और न्यायाधिकरण द्वारा बीमाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती थी। चूंकि बीमाकर्ता को न्यायाधिकरण में जाने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए ऐसा करने के लिए समय बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। यदि न्यायाधिकरण में जाने के लिए समय विस्तार के आवेदन को नियमावली के नियम 12 के प्रावधानों के तहत सक्षम माना जाता है, तो भी, अपीलकर्ता किसी भी राहत का हकदार नहीं है। क्योंकि समय बढ़ाने से

इनकार करने वाले न्यायाधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने का गुण-दोष के आधार पर कोई औचित्य नहीं है। कार्यवाही अयोग्य होने के कारण, यह जांच कि क्या इसे समय से पहले शुरू किया गया था, पूरी तरह से अप्रासंगिक होगी और इसलिए नियमों के नियम 12 की सही व्याख्या पर कोई राय व्यक्त करना अनावश्यक है। कार्यवाही शुरू से ही अक्षम होने के कारण इस न्यायालय के लिए कोई राहत देना संभव नहीं है और इसलिए, हर हाल में अपील विफल होनी चाहिए।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 82/1960

प्रकरण संख्या 16/XVI ए/1957 में जीवन बीमा न्यायाधिकरण, नागपुर न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 17 फरवरी 1958 से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

अपीलकर्ता की ओर से बी.के.बी. नायडू।

प्रतिवादी के लिए एस.टी. देसाई, एस.जे. बानाजी और के.एल. हाथी

12 अप्रैल, 1962। निम्नलिखित निर्णय सुब्बा राव और मुधोलकर, जे. जे. का निर्णय मुधोलकर, जे. द्वारा दिया गया।

सरकार जे.- आंध्र इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसे इसके बाद बीमाकर्ता कहा गया है, जीवन बीमा और अन्य बीमा व्यवसाय चलाती है। 1 सितंबर, 1956 को, बीमाकर्ता का जीवन बीमा व्यवसाय जीवन बीमा

निगम अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत भारतीय जीवन बीमा निगम में निहित हो गया। इसके बाद बीमाकर्ता अधिनियम की धारा 16 के तहत जीवन बीमा निगम से मुआवजे का हकदार बन गया।

19 फरवरी, 1957 को, निगम ने मुआवजे की राशि निर्धारित की और केंद्र सरकार की मंजूरी प्राप्त कर धारा 16 में दिए अनुसार बीमाकर्ता के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव देने वाले पत्र द्वारा, निगम ने विभिन्न कटौतियों का दावा किया। बीमाकर्ता ने कुछ विवाद उठाए। इस अपील के प्रयोजन के लिए इन विवादों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है।

6 अगस्त, 1957 को बीमाकर्ता ने 25 मई, 1957 को गठित न्यायाधिकरण में उसे देय मुआवजे के पुनर्मूल्यांकन के आदेश के लिए एक आवेदन दिया। उस आवेदन में यह प्रार्थना भी की गई कि यदि आवश्यक हो तो न्यायाधिकरण अपने गठन की तारीख से आवेदन करने का समय तीन महीने तक बढ़ा सकता है। 21 सितंबर, 1957 को बीमाकर्ता ने न्यायाधिकरण में अपने दावे का विवरण देते हुए एक और बयान दाखिल किया। निगम ने बीमाकर्ता के दावे के जवाब में अपना लिखित बयान दाखिल किया।

न्यायाधिकरण ने 17 फरवरी, 1958 के अपने निर्णय में कहा कि अधिनियम की धारा 16 के तहत बीमाकर्ता को मुआवजे की राशि के संबंध

में निगम के साथ किसी भी विवाद पर निर्णय लेने के लिए सीधे न्यायाधिकरण से संपर्क करने का कोई अधिकार नहीं है, बल्कि उसे विवाद को न्यायाधिकरण में संदर्भित करने के लिए निगम को स्थानांतरित करना चाहिए था और वर्तमान बीमाकर्ता ने ऐसा नहीं किया। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि बीमाकर्ता ने कोई कारण नहीं बताया कि न्यायाधिकरण को संदर्भ देने का समय क्यों बढ़ाया जाना चाहिए। इसने आगे कहा कि मुआवजे का दावा समय के अनुसार था। परिणामस्वरूप, न्यायाधिकरण ने बीमाकर्ता के आवेदन को खारिज कर दिया।

बीमाकर्ता ने न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए इस न्यायालय से विशेष अनुमति प्राप्त की और उस अनुमति के तहत यह अपील प्रस्तुत की है। अनुमति प्राप्त होने के बाद, बीमाकर्ता ने हिंदुस्तान आइडियल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड नामक एक अन्य कंपनी के साथ विलय कर लिया और बाद वाली कंपनी को बीमाकर्ता के स्थान पर अपीलकर्ता के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया गया।

अधिनियम की धारा 16 इन शर्तों में है:

> "(1) जहां किसी बीमाकर्ता का नियंत्रित व्यवसाय इस अधिनियम के तहत निगम को हस्तांतरित और निहित किया गया है, तो निगम द्वारा उस बीमाकर्ता को पहली

अनुसूची में निहित सिद्धांतों के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।

(2) उपरोक्त सिद्धांतों के अनुसार दिए जाने वाले मुआवजे की राशि पहले बीमा में निगम द्वारा निर्धारित की जाएगी, और यदि इस प्रकार निर्धारित राशि को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो यह बीमाकर्ता को इस अधिनियम के तहत देय मुआवजे की पूर्ण संतुष्टि में पेश की जाएगी और दूसरी ओर, यदि इस प्रकार दी गई राशि बीमाकर्ता को स्वीकार्य नहीं है तो वह इस उद्देश्य के लिए निर्धारित समय के भीतर मामले को निर्णय के लिए न्यायाधिकरण के पास भेज सकता है।"

यह धारा 16 की उपधारा (2) की शर्तों से स्पष्ट है और यह वास्तव में विवाद में नहीं है, कि बीमाकर्ता केवल निगम के माध्यम से ही न्यायाधिकरण की शरण में जा सकता है। धारा के तहत बीमाकर्ता को सीधे न्यायाधिकरण से संपर्क करने का कोई अधिकार नहीं है। जिस प्रक्रिया पर विचार किया गया है वह यह है कि बीमाकर्ता को निगम के पास जाना होगा और निगम को बीमाकर्ता द्वारा उठाए गए विवाद को न्यायाधिकरण में भेजना होगा। यह अनिवार्य रूप से धारा के शब्दों का अनुसरण करता है, अर्थात्, "वह... निर्णय के लिए मामले को न्यायाधिकरण को भेज सकता

है।" इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा में निगम का उल्लेख नहीं है, लेकिन पूरे अधिनियम से यह स्पष्ट है कि जिस संदर्भ पर विचार किया गया था वह निगम के माध्यम से था। बीमाकर्ता को संदर्भ देने के लिए किसी प्राधिकारी से संपर्क करना था और अधिनियम के तहत एकमात्र प्राधिकारी निगम हो सकता था। मामले के इस हिस्से में मैं भाई मुधोलकर के फैसले में व्यक्त विचार से सहमत हूं।

हालाँकि वर्तमान मामले में बीमाकर्ता सीधे न्यायाधिकरण की शरण में चला गया था। ऐसा करने का उसे कोई अधिकार नहीं था। इसलिए इसके द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पूरी तरह से गलत थी। ऐसा होने पर, बीमाकर्ता को न्यायाधिकरण से कोई राहत नहीं मिल सकती थी और न ही न्यायाधिकरण उसे कोई राहत दे सकता था। इसलिए, इस अपील में, बीमाकर्ता या उसके उत्तराधिकारी, अपीलकर्ता को कोई राहत देना न्यायालय के लिए संभव नहीं है। कार्यवाही शुरू से ही अक्षम होने के कारण अपीलकर्ता इसमें कोई भी अनुतोष नहीं मांग सकता।

यह देखा गया होगा कि बीमाकर्ता ने न्यायाधिकरण से समय बढ़ाने के लिए कहा था ताकि वह न्यायाधिकरण में आवेदन कर सके। चूंकि उसे न्यायाधिकरण में जाने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए ऐसा करने के लिए समय बढ़ाने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

अब अधिनियम के तहत बनाए गए नियम का नियम 12 "उस समय का प्रावधान करता है जिसके भीतर अधिनियम के तहत देय मुआवजे के निर्धारण के संबंध में न्यायाधिकरण को एक संदर्भ दिया जा सकता है।" वर्तमान मामले के लिए निर्धारित समय उस तारीख से तीन महीने था जिस दिन बीमाकर्ता को मुआवजा दिया गया था। इन तीन महीनों के भीतर बीमाकर्ता ने कुछ नहीं किया। हालाँकि, इस नियम में एक परंतुक शामिल है जो इन शर्तों में है:

> "बशर्ते कि ऐसे किसी भी संदर्भ को इस नियम के तहत निर्धारित सीमा अवधि के बाद न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार किया जा सकता है, यदि संदर्भ देने वाला व्यक्ति न्यायाधिकरण को संतुष्ट करता है कि उसके पास उक्त अवधि के भीतर संदर्भ न बनाने का पर्याप्त कारण है।"

यदि यह तर्क दिया जाता है कि बीमाकर्ता इस परंतुक के तहत सीधे न्यायाधिकरण में जाने का हकदार था और वास्तव में उसने ऐसा किया था, तो, मुझे लगता है, यह माना जाना चाहिए कि न्यायाधिकरण का विचार सही था कि बीमाकर्ता द्वारा कोई कारण नहीं दिखाया गया था कि समय क्यों बढ़ाया जाए। इसलिए यदि समय विस्तार के लिए मांगे गए आवेदन को इस परंतुक के तहत सक्षम माना जाता है, तो गुण-दोष के आधार पर भी अपीलकर्ता किसी राहत का हकदार नहीं है, क्योंकि न्यायाधिकरण ने

इस संबंध में जो आदेश दिया है, उसमें हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। किसी भी स्थिति में अपील विफल होनी चाहिए।

मैं वर्तमान मामले में परिसीमा के किसी भी प्रश्न पर जाने के लिए बाध्य महसूस नहीं करता। कार्यवाही अक्षम होने के कारण, इस बात की जांच करना कि क्या यह समय से पहले शुरू हुई थी, पूरी तरह से अप्रासंगिक होगी। इसलिए, मैं अधिनियम के तहत बनाई गई नियमावली के नियम 12 की व्याख्या पर कोई राय व्यक्त करना अनावश्यक समझता हूँ।

परिणाम यह हुआ कि अपील खारिज की जाती है। जहां तक लागत का सवाल है, मेरा मानना है कि चूँकि निगम ने स्वयं न्यायाधिकरण के समक्ष यह तर्क नहीं दिया था कि कार्यवाही अक्षम थी और न ही इस अपील में मामले के अपने बयान में ऐसा कोई मुद्दा उठाया था, इसलिए वह इसका हकदार नहीं है।

मुधोलकर, जे.- आंध्र इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, (इसके बाद कंपनी कहा गया है) एक समग्र बीमा कंपनी थी, जो जीवन बीमा, अग्नि बीमा और सामान्य बीमा का कारोबार करती थी। जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (31/1956) (इसके बाद इसे अधिनियम कहा गया है) की धारा 7(1) के प्रावधानों के तहत जीवन बीमा व्यवसाय से संबंधित इसकी सभी

संपत्तियां और देनदारियां 1 सितंबर 1956 को जीवन बीमा निगम में स्थानांतरित और निहित हो गईं। अधिनियम की धारा 16(1) के अनुसार कंपनी अधिनियम की पहली अनुसूची में विहित सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित मुआवजा निगम से प्राप्त करने की हकदार थी। 14 फरवरी, 1957 को निगम ने अन्य बातों के अलावा, कंपनी को पत्र लिखकर कहा कि निगम द्वारा निर्धारित और केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित अधिनियम की धारा 16 (एल) के तहत देय मुआवजे की राशि 6,14,636 रुपये है।निगम ने कंपनी को देय मुआवजे की पूर्ण संतुष्टि के लिए इस राशि की पेशकश की। निगम ने अपने पत्र में आगे कहा कि कंपनी की चुकता पूंजी का हिस्सा और ऐसे हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्ति, जो जीवन बीमा निगम नियम, 1956 की धारा 18 के अनुसार कंपनी के व्यवसाय के लिए आवंटित की गई राशि रु. 3,76,117/- रुपये है और चूंकि उपरोक्त संपत्ति निगम को हस्तांतरित नहीं की गई है, इसलिए 3,76,117/- रुपये की उक्त राशि कंपनी को देय मुआवजे की राशि से काट ली जाएगी। इसके बाद कंपनी और निगम के बीच कुछ पत्राचार शुरू हुआ, इससे यह प्रतीत होता है कि जबकि कंपनी ने निगम द्वारा की गई मुआवजे की राशि की गणना को स्वीकार कर लिया था, कंपनी की संपत्ति के मूल्यांकन पर पक्षकारों के बीच असहमति थी, जो निगम को हस्तांतरित हो गई थी। कंपनी ने 3,76,117/- रुपये की कटौती पर आपत्ति जताई। अंततः 6 अगस्त, 1957 को कंपनी ने केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 17(1) के तहत गठित

जीवन बीमा न्यायाधिकरण, नागपुर के समक्ष याचिका दायर की। 21 सितंबर, 1957 को कंपनी ने न्यायाधिकरण के समक्ष अपना दावा विवरण दर्ज कराया। निगम ने विभिन्न आधारों पर कंपनी के दावे का विरोध किया। न्यायाधिकरण ने 27 मुद्दे विरचित किए लेकिन उसने केवल पहले तीन मुद्दों पर ही अपने निष्कर्ष दिए और दावे को खारिज कर दिया। हम उल्लेख कर सकते हैं कि हम नंबर 3 को छोड़कर किसी भी मुद्दे से चिंतित नहीं हैं क्योंकि उसके निष्कर्ष के आधार पर ही उसने कंपनी के दावे को खारिज कर दिया। वह मुद्दा यह है कि क्या कंपनी का दावा समय से बाधित है।

निगम के लिखित बयान से ऐसा नहीं लगता कि उसने परिसीमन की दलील दी हो। फिर भी न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में कहा है कि चूंकि कंपनी ने 14 फरवरी, 1957 के तीन महीने के भीतर उसके समक्ष कोई दावा दायर नहीं किया था, यही वह तारीख थी जिस दिन निगम द्वारा कंपनी को मुआवजे की पेशकश की गई थी। यह अधिनियम के तहत बनाए गए नियमावली के नियम 12 द्वारा वर्जित था। न्यायाधिकरण ने आगे कहा कि कंपनी को न्यायाधिकरण का संदर्भ देने के लिए अधिनियम की धारा 16(2) के तहत निगम को स्थानांतरित करना था, वह ऐसा करने में विफल रही और ऐसा करने में विफल रहने के लिए उसने कोई कारण नहीं बताया, बल्कि 12 अगस्त, 1957 को सीधे न्यायाधिकरण में अपना दावा प्रस्तुत

कर दिया। इसलिए, नियम 12 के परंतुक के तहत देरी को माफ करने का कोई सवाल ही नहीं उठता।

न्यायाधिकरण के फैसले से दुखी होकर कंपनी ने अपील के लिए विशेष अनुमति देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत इस न्यायालय का रुख किया। इस न्यायालय द्वारा 18 अगस्त, 1958 को अनुमति प्रदान की गई थी। इस न्यायालय द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद कंपनी को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत अपनी योजना के अनुसरण में हिंदुस्तान आइडियल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ मिला दिया गया। इस पत्र के कारण, इसे अब इस न्यायालय के 14 अप्रैल, 1959 के आदेशों के तहत अपीलकर्ता के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

अपीलकर्ता की ओर से श्री बी.के.बी नायडू ने तर्क दिया कि चूंकि न्यायाधिकरण स्वयं नियम 12 में दिए गए तीन महीने की अवधि की समाप्ति से पहले नियुक्त नहीं किया गया था, इसलिए कंपनी द्वारा किए गए दावे को समय से बाधित नहीं माना जा सकता है क्योंकि उनके प्रस्तुतीकरण में यह सीमा उस तारीख तक शुरू नहीं होगी जिस दिन न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। वैकल्पिक रूप से उन्होंने तर्क दिया कि यह एक उपयुक्त मामला था, जिसमें नियम 12 के प्रावधान के तहत समय बढ़ाया जाना चाहिए था।

निगम की ओर से श्री एस.टी.देसाई ने तर्क दिया कि धारा 16 की उप धारा 2 के तहत कंपनी जैसे बीमाकर्ता के लिए यह खुला नहीं था कि वह ट्रिब्यूनल के समक्ष सीधे दावा पेश कर सके और कानून के अनुसार कंपनी को केवल एक संदर्भ बनाने के लिए निगम को स्थानांतरित करने का अधिकार था, यह तीन महीने के भीतर किया जाना था और वह इसके बाद निगम को नियम 12 द्वारा निर्धारित तीन महीने की अवधि के भीतर ट्रिब्यूनल को एक संदर्भ देना था। चूँकि इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया था इसलिए ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाही अक्षम थी।

धारा 16 की उप-धारा 2 इस प्रकार पढ़ता है:

> "उपरोक्त सिद्धांतों के अनुसार दिए जाने वाले मुआवजे की राशि सबसे पहले निगम द्वारा निर्धारित की जाएगी, और यदि इस प्रकार निर्धारित राशि को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो इस अधिनियम के तहत यह मुआवजे की पूर्ण संतुष्टि में बीमाकर्ता को पेश किया जाएगा, और दूसरी ओर, यदि इस प्रकार पेश की गई राशि बीमाकर्ता को स्वीकार्य नहीं है, तो वह इस उद्देश्य के लिए निर्धारित समय के भीतर मामले को निर्णय के लिए न्यायाधिकरण को भेज सकता है।"

इस प्रावधान को पढ़ने से पता चलता है कि संदर्भ बीमाकर्ता द्वारा नहीं बल्कि किसी और द्वारा दिया जाना था। हालाँकि उप-धारा 2 में किसी को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं किया गया है, संदर्भ से पता चलता है कि वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि निगम ही होगा। केंद्र सरकार ने किसी भी प्रकार से विशेष रूप से वह अवधि निर्धारित नहीं की है जिसके भीतर बीमाकर्ता को निर्णय के लिए न्यायाधिकरण को अपना दावा संदर्भित करने के लिए निगम को स्थानांतरित करना होगा।

इस प्रावधान के अनुसार बीमाकर्ता मामले को "इस उद्देश्य के लिए निर्धारित समय के भीतर" निर्णय के लिए न्यायाधिकरण में भेजने का हकदार है। "निर्धारित" का अर्थ नियमों द्वारा निर्धारित है। इसलिए, इसका अर्थ यह होगा कि केंद्र सरकार को एक नियम बनाना होगा जिसमें वह अवधि निर्धारित करनी होगी जिसके भीतर बीमाकर्ता को संदर्भ बनाने के लिए निगम को स्थानांतरित करना होगा। हालाँकि, श्री देसाई का तर्क है कि प्रावधान का यह अर्थ नहीं है। उनके अनुसार प्रावधान को अधिनियम की धारा 48(2)(एफ) के साथ पढ़ा जाना चाहिए। धारा 48 वह प्रावधान है जो केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। उपधारा 2 का खंड (एफ) उसे उस समय को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है जिसके भीतर किसी भी मामले को संदर्भित किया जा सकता है। इसलिए, विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, यह इस उद्देश्य के लिए सीमा की अवधि है जिसे केंद्र

सरकार को निर्धारित करना है, न कि वह अवधि जिसके भीतर बीमाकर्ता को न्यायाधिकरण में जाना होगा। हालाँकि, उनका तर्क है कि बीमाकर्ता को उस अवधि की समाप्ति से पहले निगम में जाना होगा जिसके भीतर निगम को न्यायाधिकरण को संदर्भ देना है।

हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते। धारा 16 की उप-धारा 2 के तहत केंद्र सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि वह उस अवधि को निर्धारित करे जिसके भीतर बीमाकर्ता को अपने दावे को न्यायाधिकरण में भेजने के लिए निगम को स्थानांतरित करना है। इसमें कोई शक नहीं, खंड (एफ) ऐसे उद्देश्य के लिए समय के निर्धारण का उल्लेख नहीं करता है । लेकिन धारा 48 की उप-धारा 1 के प्रावधान इतने विस्तृत हैं कि केंद्र सरकार इस प्रयोजन के लिए समय निर्धारित कर सकती है। उस उपधारा के तहत केंद्र सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है। अधिनियम का एक उद्देश्य उस समय को निर्धारित करना है जिसके भीतर बीमाकर्ता को संदर्भ देने के लिए निगम को स्थानांतरित करना होगा। जहां धारा 48 की उप-धारा 1 केंद्र सरकार को एक शक्ति प्रदान करती है, वहीं धारा 16 की उप-धारा 2 इस पर एक कर्तव्य लगाती है और, इसलिए धारा 48 की उप-धारा 1 तहत शक्ति का प्रयोग करके इस संबंध में एक नियम बनाना केंद्र सरकार के लिए अनिवार्य है।

इसके बाद श्री देसाई का तर्क है कि नियम वास्तव में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है, यानी नियम 12 को उस उद्देश्य के लिए पर्याप्त माना जाना चाहिए। वह नियम निम्नलिखित शब्दों में है:

> "न्यायाधिकरण को संदर्भ- वह समय जिसके भीतर अधिनियम के तहत देय मुआवजे के निर्धारण के संबंध में न्यायाधिकरण को एक संदर्भ दिया जा सकता है, वह इस प्रकार होगा, अर्थात्: -
>
> (i) किसी बीमाकर्ता के मामले में, जिसे अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग ए या भाग बी या भाग सी के तहत मुआवजा देय है, उस तारीख से तीन महीने के भीतर, जिस दिन निगम द्वारा बीमाकर्ता को निर्धारित मुआवजे की पेशकश की जाती है;
>
> (ii) ऐसे बीमाकर्ता के मामले में, जिसे अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग बी के तहत मुआवजा देय है, उस तारीख से छह महीने के भीतर, जिस दिन निगम द्वारा निर्धारित मुआवजा बीमाकर्ता को दिया जाता है;
>
> (iii) अधिनियम की धारा 36 के प्रावधानों के तहत मुख्य एजेंट या विशेष एजेंट को देय मुआवजे के मामले में, उस

तारीख से तीन महीने के भीतर, जिस दिन निगम द्वारा निर्धारित मुआवजा मुख्य एजेंट या विशेष एजेंट को दिया जाता है, जैसा भी मामला हो:

बशर्ते कि ऐसे किसी भी संदर्भ को इस नियम के तहत निर्धारित सीमा अवधि के बाद न्यायाधिकरण द्वारा स्वीकार किया जा सकता है, यदि संदर्भ देने वाला व्यक्ति न्यायाधिकरण को संतुष्ट करता है कि उसके पास उक्त अवधि के भीतर संदर्भ न बनाने का पर्याप्त कारण है।"

श्री देसाई के अनुसार, इस नियमावली के उप-नियम (1) के तहत निगम को तीन महीने के भीतर न्यायाधिकरण को एक संदर्भ देना होगा। इसलिए, उनके अनुसार, इसका अर्थ यह होगा कि बीमाकर्ता को उस अवधि की समाप्ति से पहले निगम को स्थानांतरित करना होगा और इसलिए, इस नियम को बनाकर केंद्र सरकार ने न केवल धारा 48 की उप-धारा 2 के खंड (एफ) की आवश्यकताओं को पूरा किया है बल्कि धारा 16 की उप-धारा 2 की आवश्यकताओं को भी पूरा किया है।

दो कारणों से इस तर्क को महत्व देना कठिन है। पहला यह है कि जब कानून को किसी कार्य को करने के लिए एक अवधि निर्धारित करने की आवश्यकता होती है, तो उस अवधि को विशेष उद्देश्य के विशिष्ट संदर्भ

के साथ स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। धारा 16 की उप-धारा 2 में निर्दिष्ट विशिष्ट उद्देश्य है "मामले को निर्णय के लिए न्यायाधिकरण को भेजा जाना।" इस प्रकार संदर्भ बनाना निगम के हाथ में है न कि बीमाकर्ता के, जो केवल संदर्भ बनाने के लिए निगम को स्थानांतरित कर सकता है। बीमाकर्ता द्वारा इस कार्य को करने के लिए समय निर्धारित करना आवश्यक है। संदर्भ बनाने के लिए समय निर्धारित करना निगम को संदर्भ बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए समय निर्धारित करना नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जब बाद की अवधि निर्धारित की जाती है तो यह कहना संभव होगा कि उस अवधि की समाप्ति से पहले बीमाकर्ता को निगम को स्थानांतरित करना होगा। लेकिन निहितार्थ द्वारा समय निर्धारित करना धारा 16 की उप-धारा 2 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं होगा। क्योंकि, जब किसी कार्य को करने के लिए एक अवधि निर्धारित की जाती है, तो जिस व्यक्ति को वह कार्य करना होता है, वह अंतिम दिन भी उस कार्य को करने का हकदार होता है। यदि विद्वान अधिवक्ता के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है तो इसका मतलब यह होगा कि बीमाकर्ता नियम 12 के तहत समय के भीतर होगा यदि वह उस तारीख को निगम की शरण में जाता है जिस दिन तीन महीने की अवधि समाप्त होती है। यदि वह ऐसा करता है तो निगम के लिए उसी दिन न्यायाधिकरण को संदर्भ देना कैसे संभव होगा?

विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क को स्वीकार न करने का दूसरा कारण यह है कि नियम 12 अधिकरण को उसके लिए निर्धारित सीमा अवधि के बाद एक संदर्भ स्वीकार करने का अधिकार देता है यदि "संदर्भ देने वाला व्यक्ति" न्यायाधिकरण को संतुष्ट करता है कि उसके पास निर्धारित अवधि के भीतर संदर्भ नहीं बनाने के लिए पर्याप्त कारण है। परंतुक इस प्रकार इंगित करता है कि नियम 12 के तहत न्यायाधिकरण के संदर्भ पर विचार बीमाकर्ता द्वारा किया जाना है न कि निगम द्वारा। परंतुक की भाषा से ही ऐसा प्रतीत होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नियम 12, जिसे प्रावधान के बिना माना जाता है, को निगम द्वारा दिए जाने वाले संदर्भ के लिए लागू माना जा सकता है। लेकिन प्रावधान के साथ नियम पर विचार करने से यह प्रतीत होता है कि नियम का उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिये गए संदर्भ को शासित करना था, न कि निगम द्वारा। वह व्यक्ति या तो बीमाकर्ता हो सकता है या मुख्य एजेंट या विशेष एजेंट भी हो सकता है जो धारा 36 के प्रावधान के तहत मुआवजे का हकदार है।

तब विद्वान अधिवक्ता ने एक अनोखा तर्क पेश किया। तर्क यह है कि जबकि नियम 12 के शुरुआती शब्द, एक बीमाकर्ता, एक मुख्य एजेंट या एक विशेष एजेंट उप-आरआर के रूप में निगम पर लागू हो सकते है वहीं उप-नियम (i), (ii) और (iii) केवल निगम पर लागू होते हैं, जबकि प्रावधान केवल बीमाकर्ता या मुख्य एजेंट या विशेष एजेंट, जैसा भी मामला

हो, पर लागू होता है। यदि प्रावधान, अर्थात् संपूर्ण या नियम 12 को इस प्रकार पढ़ा जाता है, विवाद आगे बढ़ता है, नियमों में कोई कमी नहीं होगी और नियम 12 का प्रावधान निरर्थक नहीं होगा।

श्री देसाई अपने इस तर्क के समर्थन में बस इतना ही कह सके कि नियम 12 के नियम (i), (ii) और (iii) को केवल निगम पर लागू किया जाना चाहिए, ताकि इस तरह के निर्माण से नियमों में खामियों से बचा जा सके। लेकिन कमी क्या है? हम पहले ही बता चुके हैं कि खामी उस समय को निर्धारित न करने में है जिसके भीतर बीमाकर्ता को संदर्भ देने के लिए निगम में जाना होगा। यदि हम विद्वान अधिवक्ता द्वारा ज़ोर दिये गए निर्माण को स्वीकार कर लें तो भी वह कमी दूर नहीं होगी। इसके अलावा, उप-नियमों की भाषा में, उन्हें केवल निगम पर लागू नहीं माना जा सकता है।

विद्वान अधिवक्ता ने तब दिया कि यदि हम नियम 12 के मूल प्रावधानों को बीमाकर्ता या मुख्य एजेंट पर लागू करने के लिए इस तरह से प्रावधान करते हैं, न कि निगम पर, तो हम मुख्य अधिनियमित प्रावधान के दायरे को सीमित कर देंगे और वह स्वीकार्य नहीं है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि जहां मुख्य प्रावधान स्पष्ट है, उसके प्रभाव को प्रावधान द्वारा कम नहीं किया जा सकता है। लेकिन जहां यह

प्रावधान स्पष्ट नहीं है, जिसे अधिशेष नहीं माना जा सकता है, वहां मुख्य प्रावधान के अर्थ और दायरे को ठीक से देखा जा सकता है। इस प्रयोजन के लिए परंतुक को देखने से विद्वान वकील द्वारा उल्लिखित निर्माण के नियम का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

वेस्ट डर्बी यूनियन बनाम मेट्रोपॉलिटन लाइफ एश्योरेंस कंपनी में ((1897) ए.सी. 641, 652) लॉर्ड वॉटसन ने कहा:

> "..... मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूं कि ऐसे कई मामले हो सकते हैं और हैं जिनमें एक बोधगम्य परंतुक की शर्तें वैधानिक शब्दों के अस्पष्ट आयात पर काफी प्रकाश डाल सकती हैं।"

उसी मामले में लॉर्ड हर्शेल ने स्वीकार किया कि अधिनियम में शब्दों के दो संभावित निर्माणों में से एक या अन्य के चयन में या किसी संदिग्ध मामले में बाद के दायरे को दिखाने के लिए एक प्रावधान एक उपयोगी मार्गदर्शिका हो सकता है। यहां हम पाते हैं कि नियम 12 अपने आप में स्पष्ट रूप से नहीं दिखाता है कि यह निगम के विशेष एजेंट को अपील करता है या नहीं। इसलिए, नियम 12 के मुख्य प्रावधानों के दायरे को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान पर गौर करने की अनुमति है। जैसा कि हमने पहले कहा है, उचित निर्माण होने पर प्रावधान निगम पर लागू नहीं

हो सकता। इसलिए, जब हम नियम 12 को समग्र रूप से पढ़ते हैं, अर्थात, परंतुक के साथ हम किसी भी स्वीकृत नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे हालांकि इसे पढ़कर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि धारा 12 केवल बीमाकर्ता या मुख्य एजेंट या विशेष एजेंट पर लागू होती है, निगम पर नहीं।

हम आगे बता सकते हैं कि प्रावधान बेकार हो जाएगा यदि हम मानते हैं कि नियम 12 केवल निगम द्वारा दिए गए संदर्भ से संबंधित है। हम यह क्यों कहते हैं कि यह बेकार हो जायेगा, इसका कारण यह है। मान लीजिए कि कोई बीमाकर्ता संदर्भ बनाने के लिए तीन महीने से अधिक समय के बाद निगम की ओर रुख करता है, तो क्या निगम संदर्भ देने के लिए बाध्य होगा? धारा 16 की उप-धारा 2 की शर्तों पर निगम केवल तभी एक संदर्भ देने के लिए बाध्य होगा यदि बीमाकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर उसकी ओर रुख किया जाता है। यदि ऐसा है, तो बीमाकर्ता को देरी को माफ करने के लिए न्यायाधिकरण में जाने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। हालाँकि, श्री देसाई के अनुसार, निगम को संदर्भ देने के लिए परमादेश द्वारा बाध्य किया जा सकता है। इसका संक्षिप्त उत्तर यह है कि नियम 12 द्वारा निर्धारित अवधि की समाप्ति या अवधि के बाद संदर्भ देने का निगम पर कोई कर्तव्य नहीं है, कोई परमादेश जारी नहीं कर सकता है।

विद्वान अधिवक्ता के तर्क को स्वीकार न करने का एक अन्य कारण यह है कि परंतुक में संदर्भ देने वाले व्यक्ति द्वारा ट्रिब्यूनल को संतुष्ट करने

की बात कही गई है कि उसके पास उसी अवधि के भीतर संदर्भ न बनाने का पर्याप्त कारण है। यदि बीमाकर्ता संदर्भ देने वाला व्यक्ति नहीं है, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि उसे संदर्भ देने में देरी को माफ करने के कारण की पर्याप्तता के बारे में ट्रिब्यूनल को संतुष्ट करने की अनुमति दी गई है? हालाँकि, श्री देसाई का सुझाव है कि हमें "यदि संदर्भ देने वाला व्यक्ति न्यायाधिकरण को संतुष्ट करता है... आदि" शब्दों को पढ़ना चाहिए। जैसे कि वे पढ़ते हैं "यदि जिस व्यक्ति के कहने पर संदर्भ दिया गया है, वह न्यायाधिकरण को संतुष्ट करता है... आदि।" यह उस प्रावधान को फिर से लिखना होगा जो हम नहीं कर सकते।

हमें ऐसा लगता है कि नियम 12 विरचित करते समय नियम बनाने वाले प्राधिकारी ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि धारा 16 की उप-धारा 2 बीमाकर्ता द्वारा नहीं बल्कि निगम द्वारा एक संदर्भ पर विचार करता है। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि हमें नियम पर ऐसी व्याख्या नहीं करनी चाहिए जो अधिनियम के कामकाज में गंभीर कमी छोड़ दे। हम उनके तर्क की सराहना करते हैं, लेकिन परिणाम से कोई बच नहीं सकता।

न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही गलत समझी गई क्योंकि उन्हें शुरू करने का एकमात्र तरीका निगम द्वारा एक संदर्भ था और ऐसा कोई संदर्भ नहीं दिया गया था। सीमा का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि वह अवधि जिसके भीतर बीमाकर्ता को संदर्भ बनाने के लिए निगम की ओर

रुख करना होगा, अभी तक धारा 16 की उप-धारा 2 के अनुसार निर्धारित नहीं किया गया है। अपीलकर्ता के लिए यह खुला होगा कि वह धारा 16 की उप-धारा 2 के तहत निर्धारित अवधि में निगम का सहारा ले सकता है।

हम न्यायाधिकरण के समक्ष सभी कार्यवाहियों को रद्द करते हैं लेकिन विशेष परिस्थितियों में लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील खारिज

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' के जरिए अनुवादक खुशबू सोनी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय वादी के प्रतिबंधित उपयोग के लिए उसकी भाषा में समझाने के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।